

जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं, तो उन्होंने एआईसीसी के सब दरवाजे खुलवा दिये थे, जिससे जनता उनसे मिल सके

अब, कांग्रेस फिर एक के बाद एक चुनाव हार रही है, पर, कांग्रेस मुख्यालय के सभी दरवाजे बंद करवा दिये गये हैं। जनता का प्रवेश इस मुख्यालय में केवल इजाजत व पूर्व अपॉइन्टमेंट से ही हो सकता है

-नेरू मित्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थीं, तो उन्होंने अपने स्टाफ को अपने घर के दरवाजे खुले रखने के आदेश दे दिये, ताकि जो व्यक्ति उनसे मिलना चाहे, वह अन्दर आ सके।

2025 में राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अलग प्रकार की पार्टी है। नये कांग्रेस मुख्यालय के द्वार और दरवाजे पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा मीडिया के लिये बंद कर दिये गये हैं और विडाम्बना यह है कि इसका नाम इन्दिरा भवन रखा गया है।

साइनबोर्ड पर लिखा है: बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। नवनिर्वाचित सिक्योरिटी गार्ड किसी को पहचानते नहीं हैं। इसलिये, और तो और, हरि प्रसाद जैसे वरिष्ठ नेता को रोक दिया गया, उन्हें अन्दर नहीं जाने दिया गया।

नये मुख्यालय में राज्य-वार मीटिंग हो रही हैं। लेकिन मुझे भर नेताओं को ही अन्दर जाने दिया जा रहा है। अन्य नेताओं को बाहर ही ठहरने को कह दिया जाता है।

ये नये आदेश किसने दिये हैं, क्योंकि ये तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के चिन्तन से एकदम विपरीत हैं।

मुख्यालय की नई बिल्डिंग में लागू इस नई व्यवस्था से आम जनता व कार्यकर्ता अपने नेताओं से कटते जा रहे हैं।

आम कार्यकर्ता नेताओं के इस आचरण से कुपिठत तो हैं ही, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि पार्टी क्या मैसेज देना चाह रही है।

कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार भी परेशान हैं, उनकी प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही नए भवन में एंट्री हो पाती है, और यह एंट्री भी ग्राउण्ड फ्लोर तक ही सीमित है। हाल ही में एक महिला पत्रकार को भाग कर पुराने मुख्यालय, 24, अकबर रोड, जाना पड़ा, "वॉशरूम" का उपयोग करने के लिये।

24 अकबर रोड कार्यालय वाले स्टाफ को नये मुख्यालय में शिफ्ट नहीं किया गया है। वहाँ उनके पास कोई खास काम नहीं है, क्योंकि नेतागण वहाँ नहीं होते।

महासचिवों तथा राज्य प्रभारियों से

धीरे-धीरे कार्यकर्ताओं से दूर होते जा रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे कि वे अपने नेताओं से कैसे मिलें तथा इस व्यवस्था की शिकायत किससे करें।

कोई कार्यकर्ता या नेता, जो अपने निजी काम से या अन्य किसी कारण से दिल्ली आता था, तो एआईसीसी मुख्यालय, 24 अकबर रोड जरूर जाता था तथा अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिला करता था, जिनमें से अधिकांश लोग कार्यालय के लॉन में इकट्ठे हो जाया करते थे।

गुलाम नबी आजाद जैसे वरिष्ठ नेता अपना अधिकांश समय लॉन में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने में गुजारते थे, जिससे कि कार्यकर्ताओं को यह संतुष्टि मिले कि वे किसी वरिष्ठ नेता से मिल लिये हैं।

नए भवन में मीडिया उस समय तक भवन में प्रविष्ट नहीं हो सकता, जब तक आमंत्रित न किया गया हो। आमंत्रण की स्थिति में भी, पत्रकार ग्राउंड फ्लोर पर स्थित ब्रीफिंग रूम तक ही जा सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आबू रोड के पास ट्रोला और कार की टक्कर में 6 की मौत

जालोर/आबूरोड, 6 मार्च (का.सं.)। सिरौही जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के किवरली के पास गुरुवार सुबह करीब 3 बजे एक दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई तथा एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद सिरौही रेफर किया गया है। जानकारी मिलने पर सीओ गोमाराम, सदर थानाधिकारी दर्शनसिंह, एसआई गोकुलराम, हैड कांस्टेबल विनोद सहित, पुलिस

कार अहमदाबाद से जालोर आ रही थी, जब उसकी आगे चलते ट्रोला से टक्कर हुई।

मृतकों के शव को बाहर निकालने के लिये कार के दरवाजे तोड़े गये। करीब 40 मिनट की मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका।

अधिकारी मौके पर पहुंचे।

सीओ गोमाराम ने बताया कि जालोर निवासी लोग कार में सवार होकर अहमदाबाद से जालोर आ रहे थे। नेशनल हाइवे 27 पर किवरली के पास आगे चल रहे ट्रोले से कार की टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है तथा परिजनों को सूचना दे दी गई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फ्रांस ने अच्छी तरह से अमेरिका को अंगूठा दिखाया और दादागिरी स्वीकार करने से साफ इन्कार किया

फ्रांस ने रूस के खिलाफ "न्यूक्लियर हथियारों" के रक्षा कवच में पूरे यूरोप को शामिल किया तथा एक तरह से "नाटो" का विकल्प प्रस्तुत किया

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। डॉनल्ड ट्रम्प और अमेरिका ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। लेकिन फ्रांस ने अमेरिका से अलग होने की घोषणा कर दी है और अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए फ्रांस ने अमेरिका के अस्थिर बुद्धि राष्ट्रपति के आगे झुकने से इंकार कर दिया है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका को अपने निकटतम यूरोपियन सहयोगी से इतना बड़ा झटका मिला है। फ्रांस ने रूस की तरफ से होने वाले हमलों से सुरक्षा के लिए अपने न्यूक्लियर हथियारों व रक्षा कवच को अपने तक सीमित न रखकर यूरोप के सभी देशों को इसमें शामिल किया है। यह रूस के खिलाफ नाटो (एन.ए.टी. ओ.) की साझा डिफेंस रणनीति का फ्रांसीसी विकल्प है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने देश की रणनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रभु सत्ता की घोषणा की, जो कि अन्य सम्प्रभु देशों को दबाने की अमेरिका की नीति के एकदम उलट है। यह अमेरिका के नेतृत्व में नाटो के तहत बने वैस्टन सिक्युरिटी एवं डिफेंस गठबंधन से एक

साथ ही, जर्मनी, इंगलैण्ड, फ्रांस ने यूरोप के अन्य मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिये शांति प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। दूसरी ओर अमेरिका ने सऊदी अरब में रूस के साथ बैठकर, बिना यूक्रेन को शामिल करे, यूक्रेन में युद्ध समाप्ति का समाधान "हूद" लिया। इस बैठक में यूरोप के किसी अन्य देश को आमंत्रित नहीं किया गया था।

अमेरिका ने यूक्रेन की खनिज सम्पदा के दोहन का पुरा प्लान बना लिया, बिना यूक्रेन की रजामंदी व स्वीकृति के।

फ्रांस व यूरोप के अन्य देशों के, मिल बैठकर तैयार किए गए "पीस प्लान" की प्रक्रिया में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है, बाहर रखा गया है।

फ्रांस ने यह भी वादा किया है कि एक बार शांति स्थापित हो गई तो वह यूक्रेन की सहायता के लिये अपने सैनिक भी भेजेगा।

तहर की खुली बगावत है।

इन्टरनेशनल न्यूज चैनल सी.एन.एन. के अनुसार, मैक्रों ने फ्रांस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में कहा कि "हमारा परमाणु निरोधक कवच हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यह संपूर्ण है और

सम्प्रभु है।"

उन्होंने आगे कहा कि जो भी स्थिति हो, निर्णय हमेशा रिपब्लिक के राष्ट्रपति, जो सेना का कमांडर भी हैं, के हाथ में रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हजारों भारतीय युवाओं पर "डिपोर्टेशन" की तलवार लटकी'

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। अमेरिका के वर्तमान माइग्रेशन कानूनों के तहत ऐसे हजारों भारतीयों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है जो 21 वर्ष के होने जा रहे हैं और जो एच-4 वीसा के तहत अमेरिका आए थे। ये सैल्फ डिपोर्टेशन के खतरे के साए में रह रहे हैं क्योंकि वे अपने एच- वन बी वीसा होल्डर माता-पिता पर निर्भर नहीं माने जायेंगे।

अभी तक उनके पास दो साल थे 21 का होने के बाद वीसा ट्रांज़िशन के लिए, पर इमिग्रेशन नीति में हालिया बदलाव के बाद उनका भविष्य संदेह के घेरे में आ गया है।

पता चला है कि इनमें से अधिकांश अन्य विकल्प तलाश रहे हैं जिनमें से केनडा व ब्रिटेन जाने का विकल्प भी है, जहाँ इमिग्रेशन नीतियां काफी लचीली हैं। अमेरिका के रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड सिस्टम में भारी बैकलॉग है, जो भारतीय अप्रवासियों को गैर आनुयातिक के रूप में प्रभावित कर रहा है।

यूएस सिटीजनशिफ एण्ड इमिग्रेशन सर्विसेज (यू.एस.सी.आई.)

हजारों भारतीय मूल के युवा जो अब इक्कीस साल के होने वाले हैं, तकनीकी रूप से अपने एच-वन बी वीजाधारी व अमेरिका में कार्यरत माँ-बाप पर "डिपैन्डेंट" नहीं रह गये। अतः, वे "डिपोर्ट" किये जा सकते हैं, चाहे वे अपने माँ-बाप के साथ कितने ही वर्षों से अमेरिका में रह रहे हों।

अब तक इन भारतीय युवाओं के पास एक विकल्प था कि वे दो साल में अगर अमेरिका में रोजगार पा जाते थे, तो उनके वीजा में "डिपोर्टेशन" की शर्त हट जाती थी।

पर, अब राष्ट्रपति ट्रम्प की नई पॉलिसी के अंतर्गत, यह दो साल की अवधि खत्म कर दी गई है।

एस.) ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के लिए एच-वन बी वीसा के रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। प्रक्रिया 7 मार्च से खुलेगी और 24 मार्च तक चलेगी। यह वीसा गैर इमिग्रेंट वीसा है इसके तहत अमेरिकन कम्पनियों विदेशी नागरिकों को नियुक्ति देती हैं। एक साल में ज्यादा से ज्यादा 65000 एच-वन बी वीसा दिए जा सकते हैं जिसमें अमेरिका से मास्टर्स डिग्री लेने वालों के लिए 20,000 की वृद्धि की जा सकती है। यूएससीआईएस

ने एक लाभार्थी केन्द्रित चयन प्रक्रिया शुरू की है ताकि फर्जीवाड़ा कम हो सके निष्पक्ष चयन सुनिश्चित हो। नई रजिस्ट्रेशन फीस 215 डॉलर है।

मार्च 2023 को टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 1.34 लाख भारतीय बच्चे, उनके परिवारों को ग्रीन कार्ड मिलने से पहले, डिपैन्डेंट वीसा की उम्र को पार करने की स्थिति में आने वाले थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली, 06 मार्च। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह में फैसला लेने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बयान के बाद दिया है। सरकार की ओर से दिए गए बयान में कहा गया है कि हवाई जहाज के किराए को लेकर

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हज यात्रा के महंगे एयर टिकट पर 7 दिन में फैसला लेने का निर्देश दिया है।

उठाए सवाल के आधार पर जांच की जाएगी। सरकार के निर्णय के कारणों को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ताकि यह दिखाया जा सके कि कालीकट से जेद्दा की हज यात्रा केरल के अन्य जगहों से की जाने वाली यात्रा की तुलना में अधिक महंगी क्यों है? हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात पर विवाद नहीं है कि किराया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भाषा विवाद!

विवाद की शुरुआत हुई, वरिष्ठ आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी की टिप्पणी से

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 6 मार्च। तमिलनाडु के बाद, अब भाजपा-शासित महाराष्ट्र में भी भाषा विवाद पनपता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आरएसएस नेता सुरेश भैया जी जोशी का यह बयान था कि "मुम्बई आने वाले किसी व्यक्ति के लिये मराठी सीखना आवश्यक नहीं है।"

भाषा के प्रश्न पर अति संवेदनशीलता तथा सभी राजनैतिक दलों के राजनेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाओं के चलते, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस को विधानसभा में खड़े होकर यह कहना पड़ा कि "मराठी मुम्बई और महाराष्ट्र की भाषा है तथा यहाँ रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मराठी

भैयाजी ने कहा कि "अगर कोई बाहर से मुम्बई आता है, उसके लिये जरूरी नहीं है, वह मराठी सीखे।"

उद्धव ठाकरे ने इस टिप्पणी के बाद सार्वजनिक मांग की कि भैयाजी जोशी पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिये तथा उनकी टिप्पणी महाराष्ट्र का अपमान है। ठाकरे ने आगे इस संदर्भ में कहा, केवल इसलिये कि "मराठी मानुस, सबका स्वागत करता है, इसका मतलब यह नहीं कि कोई उसको थप्पड़ मार सकता है।"

विवाद इतना बढ़ा कि मु.मंत्री फडनवीस को विधानसभा में खड़े होकर कहना पड़ा कि "मराठी, मुम्बई की व महाराष्ट्र की भाषा है और जो भी व्यक्ति यहाँ रहता है, उसे यह भाषा बोलना, सीख लेना चाहिये।"

बोलना सीखना चाहिये।"

भाषा के मुद्दे पर आरएसएस नेता

के बयान पर विपक्षी एमवीए (महाराष्ट्र विकास अथाडी) के नेतृत्व में भारी विरोध फूट पड़ा तथा मराठी की प्रमुखता पर जोर देने वाले नारे लगाये जाने लगे। शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ने मांग की कि जोशी को राजद्रोह के जर्म में गिरफ्तार किया जाना चाहिये। उन्होंने जोर देते हुये कहा कि उनका बयान "महाराष्ट्र के अपमान" के बराबर है।

शिव सेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने पूछा: "क्या वे (भैयाजी) कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, लुधियाना, पटना, बंगलुरु, त्रिवेन्द्रम या हैदराबाद जाकर, ऐसा बोल सकते हैं?"

मुख्यमंत्री ने एक स्पष्टीकरण जारी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सबसे पहले लाइफ इश्योरिस



एलआईसी का जीवन उत्सव

Plan No.: 771 UIN: 512N363V02

उत्सव मनाने का गारंटीड तरीका



आजीवन गारंटीड रिटर्न के साथ

ऑनलाइन भी उपलब्ध

पूर्ण आयु जीवन बीमा एवं लाभ भुगतान के विकल्प

- सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि 5 से 16 वर्ष
- प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान गारंटीकृत वृद्धि
- नियमित आय लाभ / फ्लेक्सि आय लाभ
- न्यूनतम मूल बीमा राशि 5 लाख

एक नॉन-पार, नॉन-लिंक्ड, व्यक्तिगत, बचत, पूर्ण आयु जीवन बीमा योजना

आयुष्मानि कर्ष एलआईसी मोबाइल ऐप LIC India

वित्तित्त कर: licindia.in

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

हमारा कॉलसर्विस नं. 8976862090

भारतीय जीवन बीमा निगम LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेंट/मिडिल्टर एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने सहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

धोखाधड़ी वाले फोन कॉल तथा झूठे/भ्रमक प्रस्तावों से सावधान रहें, ऑनलाइन/ऑफ़ लाइन या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बीमा की घोषणा या प्रीमियम के भिन्न, राशिगत लौटाने जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं जिन पॉलिसीधारकों या सम्पत्ति ग्राहकों को ऐसे फोन कॉल मिलें, 3 कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें, कृपया बिक्री के सम्पन्न से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें.

विचार बिन्दु

जीवन में सबसे अच्छा दोस्त वह है, जो आपको सर्वश्रेष्ठ बाहर लाता है। -हेनरी फोर्ड

आवश्यकता है, चुनाव कानूनों में बदलाव की

परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ही जीवन के विकास का नियम है। परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है। परिवर्तन के कारण ही जीव का जन्म होता है। भगवान कृष्ण ने गीता में संदेश दिया कि परिवर्तन संसार का अटल नियम है। यह सार्व भौमिक है। अतः कानून में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। यह समय की पुकार है। कानूनों में सुधार करना संशोधन करना विकास के लिये अति आवश्यक है। संविधान में भी अनुच्छेद 368 में संशोधन की विशद विवेचना तथा प्रक्रिया दी है। भारत के संविधान में अब तक 102 संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो चुके हैं और अनेक पाइप लाइन में हैं।

भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उसने अपने लिये एक संविधान बनाया जो 26 जनवरी, 1950 से लागू किया गया। संसद व विधान सभाओं में कानून बनते हैं और समय-2 पर उनमें संशोधन होते हैं तथा आवश्यकता न रहने पर वे रिपील भी कर दिये जाते हैं।

भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ सरकार का गठन चुनावों की प्रक्रिया से होता है। स्वतंत्र चुनाव कमीशन कराता है जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसे कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका के अधिकार प्राप्त हैं। चुनाव के लिये चुनाव कानून है। मतदान से चुनाव होता है। कानून से मतदाता लिस्ट बनाई जाती है। चुनाव के लिये प्रमुख कानून लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 है। इस कानून के अनुसार संसद व विधान मण्डलों के सदस्यों के हेतु चुनाव कराने की प्रक्रिया दी गई है। संविधान लागू होने के 75 वर्षों में देश में काफी परिवर्तन हो चुका है। इसलिये समय के साथ हमें अपने कानूनों में भी परिवर्तन/संशोधन लाना होगा। बांग्लादेश पड़ोसी देश के लोग भारत में अनाधिकृत प्रवेश कर रहे हैं। फर्जी रूप से मतदाता बनकर चुनावों में मतदान कर रहे हैं और चुनावों के रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। डिजिटलाइजेशन व एआई के कारण कई परिवर्तन हो रहे हैं। देश में अब किसी न किसी भाग में चुनाव हो रहे हैं। देश में पूरे वर्ष चुनाव का वातावरण बना रहता है। इसके कारण विकास के कार्य रूक जाते हैं। आवश्यकता है 'एक देश एक चुनाव' की। कैसे इस समस्या से निपटा जावे, इस बाबत संसद में बिल भी पेश हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि एक देश एक चुनाव प्रस्ताव 2029 से पहले संसद में पारित हो जावेगा, किन्तु कई कठिनाईयाँ इसके मार्ग में हैं। चुनाव में कई तरह के खर्चें बढ़ रहे हैं। साथ ही प्रशासनिक लागत में भारी बढ़ोतरी हो रही है। फ्रीबीज के कारण सरकारों का बजट राज्य को कंगाल कर रहा है। मशीनों के स्थान पर पेंपर बलेट की ओर वापिस आने की बात कुछ राजनीतिक पार्टियाँ उठा रही हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ईवीएम मशीनों की प्रमाणिकता पर मुहर लगा चुकी है।

परिसीमन के प्रश्न पर कनेटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थमैया केन्द्रीय सरकार के विरोध में सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। उनके अनुसार परिसीमन की कवायद के द्वारा केन्द्रीय सरकार दक्षिण भारत के राज्यों की सीटों व राजनीतिक प्रभाव कम करने जा रही है। प्रस्तावित परिसीमन पर वार्ता के लिये तामिलनाडू के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन 5 मार्च, 2025 को सर्वदलीय बैठक आहूत कर रहे हैं। उनका आंकलन है कि तामिलनाडू को आठ सीटों का नुकसान होगा, यदि जनसंख्या देश पर आधारित यह कार्य किया गया। सीटें 39 हैं, वे घटकर 31 रह जावेंगी। सर्वदलीय बैठक में अनाद्रमिक और पीएमके जैसे दल बैठक में भाग लेंगे, किन्तु भाजपा और उसके घटक दल इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। इस प्रसंग का उल्लेख केवल इसलिये किया गया है कि चुनाव सम्बन्धित सभी विषयों में कानून का अस्पष्टता के कारण विवाद पैदा हो रहे हैं। चुनाव में फर्जी मतदाता सूचियों का उल्लेख होता है तो कुछ राजनीतिक पार्टियाँ एक दूसरी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाती हैं कि मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम काटे व जोड़े जा रहे हैं।

चुनाव कमीशन के समक्ष कई विवाद चल रहे हैं। यह भी विवाद है कि दो अलग-2 राज्यों के मतदाताओं के वोटर कार्ड पर एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड (पहचान पत्र) नम्बर को लेकर विवाद है। आयोग ने इसका स्पष्टीकरण दिया है कि एक जैसे एपिक नम्बर का अर्थ यह नहीं है कि लिस्ट में फर्जी मतदाता हैं।

दिल्ली के चुनावों में वोटर्स लिस्टों को चुनौती दी गई है। फर्जी वोटर्स का आरोप लगाया है। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध संगीन अपराध के केसेज चल रहे हैं, उन्हें चुनाव में खड़ा किया जाता है। उम्मीदवार के लिये शिक्षित होने की कोई शर्त नहीं है। कई बातें जो नोमिनेशन प्रपत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है, उसका कोई अर्थ नहीं है। नामांकन पत्र में शिक्षा का कॉलम है, किन्तु अशिक्षित होने पर भी वह खड़ा हो सकता है। मुकदमें (फौजदारी) चल रहे हैं फिर भी इस आधार पर व्यक्ति को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है।

संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य परिभाषित अनुच्छेद 51क में किये गये हैं; किन्तु उसकी पालना न होने पर भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। मूल कर्तव्यों में प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की गई है कि वह हिंसा से दूर रहेगा, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करेगा। देश में कहीं भी आन्दोलन हो, सरकारी वाहनों व सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है, सड़कें तोड़ी जाती हैं, आगजनी होती है और रेल्वे की लाइनें उखाड़ी जाती हैं और जनता का मार्ग अवरोध किया जाता है। कर्तव्यों में यह अपेक्षा की है कि प्रत्येक नागरिक भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, किन्तु हमारा आचरण इसके विपरीत है। क्या ऐसे व्यक्ति संसद सदस्य अथवा विधानसभा के सदस्य होने चाहिये?

समय की पुकार है हमें हमारे चुनाव कानूनों को देश के विकास के लिये नई सोच के अनुरूप बनाना होगा। अतः आवश्यकता है हम चुनाव कानून में संसद सदस्य/विधानसभा के सदस्य के लिये योग्यता (Qualification) का निर्धारण करें। कानून बनाने वाला कम से कम बी. ए. तो पास होना ही चाहिये। इसी प्रकार आरोप्यता (Disqualification) भी निर्धारित होने चाहिये। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों की पालना ही नहीं कर पा रहा है उसे आप कानून बनाने वाला कैसे बना सकते हैं?

चुनाव कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि चुनाव सम्बन्धित विवाद केवल चुनाव हो जाने के बाद ही एक विशेष ट्रिब्यूनल निर्धारित करे। इन दिनों यह देखने में आ रहा है संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 के अधिकार के हेतु पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इस पर अंकुश होना चाहिये। मतदाता सूची के मामले राज्य के चुनाव अधिकारी द्वारा तय किये जाने चाहिये और उसका निर्णय 15 दिनों में होना चाहिये।

इन दिनों फ्रीबीज की सुविधाओं की बाढ़ आ रही है। फ्रीबीज एक प्रकार से वोट प्राप्त करने के हेतु रिश्ता ही है। इसका बंद होना आवश्यक है। केश बेनीफिट देना और मत प्राप्त करना अनैतिक है, इसके हेतु सजा का प्रावधान होना चाहिये। दायी व्यक्तियों को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार देना उचित नहीं है। संक्षेप में लेखक का अनुरोध है कि नया चुनाव कानून शीघ्र लाया जावे। 10वीं क्लास के बालक को चुनाव कानूनों का तथा संविधान का सामान्य ज्ञान देना चाहिये।

प्रश्न: यह देखने में आया है कि चुनाव याचिकाओं का निर्णय चुनाव की अर्वाधि समाप्त होने तक नहीं होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश को चुनाव पिटीशन की सुनने का अधिकार दिया है, उनके पास अपना कार्य करने के लिये भी समय नहीं होता, फिर वे कैसे न्याय कर सकते हैं? संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जिन्हें 'Sunset Law' के नियम के अनुसार लागू करना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद 334 में स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है इस प्रावधान में यह व्यवस्था है कि लोकसभा में और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण होगा, किन्तु यह कहा गया है कि इस संविधान के उपबन्ध इस संविधान के प्रारम्भ से 10 वर्ष की अर्वाधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इसका अर्थ है कि आरक्षण 10 वर्ष बाद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और 10 वर्ष के स्थान पर प्रत्येक 10 वर्ष में बढ़ा दिया जाता है। आज यह प्रावधान 10 के स्थान पर 80 हो गया है। इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट में तथा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है; किन्तु आज तक सुनवाई इस पर नहीं हुई। सम्भवतः लगभग 20 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है।

संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का उल्लेख है। इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 37 में केवल यह स्पष्ट किया है कि इन तत्वों को कोई न्यायालय प्रवर्तनीय नहीं कर सकेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि नीति निदेशक तत्वों की क्रियान्विति के लिये बनाई जाने वाली विधि मूल अधिकारों से असंगत नहीं होगी। वस्तुतः नीति के निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। लेखक के मत के अनुसार यह व्यवस्था कुछ समय के लिये थी, किन्तु इसके कारण संविधान की अवज्ञा नहीं की जा सकती। समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का कर्तव्य है 75 वर्षों के बाद भी इसे लागू न करना संविधान की अवमानना है। संवैधानिक दृष्टि से भाग 4 में वर्णित कर्तव्य भाग 3 के मूलभूत अधिकारों से भिन्न नहीं है। भाग 3 के मूल अधिकार राजनीतिक मूल अधिकार हैं और भाग 4 के कर्तव्य राज्य के सामाजिक व आर्थिक कर्तव्य हैं।

संविधान के कई अनुच्छेद जिनमें अनुच्छेद 334, 343, 44, 45, 48ए, 50 आदि को हमें विकसित भारत की दृष्टि से देखना होगा। अतः भारत की जनता, राज्य से अपेक्षा करती है कि चुनाव कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है और शीघ्र से शीघ्र चुनाव कानून नई कानूनी सोच के अनुसार बने अथवा उनमें संशोधन हो। भविष्य में आने वाले चुनाव तक भारत को विकसित देश बनाने का राष्ट्र का संकल्प होना चाहिये।

गत कई वर्षों से संसद व विधान सभाओं में हंगामे व शोरगुल में ही समय नष्ट होता है और सतत व समग्र विकास का कार्य नहीं होता, नये भारत के निर्माण के कार्य को गति प्राप्त होनी चाहिये। अतः नियम बनाना चाहिये सदन में बहस हो, चर्चा हो, किन्तु शोरगुल व हंगामा तथा असभ्य भाषा का प्रयोग न हो और ऐसा करने वाले सदस्यों को सत्र से निष्कासित माना जावे और पूरे सत्र का भत्ता न दिया जावे। मेरे देश तेरी जय हो, जय हो, जय हो।

-अतिथि सम्पादक, पानाचन्द्र जैन पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

किशोरों की आवाज़ : स्वास्थ्य सेवा मूल्यांकन में किशोरों की भागीदारी

किशोरों को आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में उजाला क्लिनिक सेवाओं के मूल्यांकन में कार्यशाला द्वारा शामिल किया

किशोरोपस्था मानव के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें कई विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना होता है किन्तु जब किशोरोपस्था के संदर्भ में खास स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया जाता है तो विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाई गई हैं, तो किशोरों की आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। जनवरी-मार्च 2024 के बीच किए गए एक सहभागी शोध अध्ययन ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिसमें किशोरों को आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में उजाला क्लिनिक सेवाओं के मूल्यांकन में कार्यशाला द्वारा शामिल किया गया।

इस अध्ययन में 15-18 वर्ष की आयु के किशोरों को शामिल किया गया, जो तीन स्थानीय स्कूलों- विद्या भवन पब्लिक स्कूल, विद्या भवन सीनियर सेकेडरी स्कूल और सीडिलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल से थे। इन किशोरों ने क्लिनिक की सेवाओं का मूल्यांकन करने में सक्रिय भूमिका निभाई। वे केवल उपभोक्ता नहीं थे, बल्कि उन्होंने मूल्यांकन को डिजाइन करने, प्रश्न तैयार करने और एकत्र किए गए डेटा का प्रारंभिक विश्लेषण करने में भी योगदान दिया। किशोरों द्वारा पहचानी गई प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी विषयों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कि चिंता, अवसाद और पारिवारिक दबाव शामिल थे।



उन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर की छवि (बॉडी इमेज) और व्यायाम/फिटनेस की कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त की। यौन स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि कई किशोर खुद को गर्भ निरोधक उपायों और यौन संचारित रोगों की जानकारी के मामले में अज्ञान और अनभिज्ञ महसूस कर रहे थे।

प्रतिभागियों ने उजाला क्लिनिक के भौतिक वातावरण को लेकर भी समस्याएँ उठाईं, जिसमें सफाई की कमी और निजता के अभाव को मदद

लेने में प्रमुख बाधा बताया गया। क्लिनिक के मंद रोशनी वाले माहौल की ओर इशारा करते हुए एक प्रतिभागी ने बोला, उजाला क्लिनिक में कोई 'उजाला' नहीं है, हालाँकि, कर्मचारियों के साथ बातचीत ज्यादातर सकारात्मक रही। किशोरों ने उजाला क्लिनिक के कर्मचारियों की मित्रवत, सहनशीलता और सहायक प्रकृति की बहुत सराहना की।

एक प्रतिभागी ने साझा किया, मुझे नहीं लगा था कि उजाला क्लिनिक में मैं हूँ, लेकिन इस बार हमने सवाल पूछे हैं और रचनात्मक

शांतिपूर्वक हमसे बात करेगी। उन्होंने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। इस स्वागतपूर्ण रवैये ने किशोरों को संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने में सहज महसूस कराया।

इस अध्ययन के सहभागी दृष्टिकोण ने किशोरों को प्रेरित किया और उन्हें अपने स्वास्थ्य सेवा अनुभवों पर अधिक नियंत्रण का अनुभव करने का अवसर दिया। एक प्रतिभागी ने कहा, अगर कोई आता है, तो वे हमसे सवाल पूछते हैं, लेकिन इस बार हमने सवाल पूछे हैं और रचनात्मक

गतिविधियाँ, जैसे कि रोल-प्ले, समूह चर्चा और संगीत, विशेष रूप से सराहे गए। एक प्रतिभागी ने कहा, हमें चार्ट बनाना और अलग-अलग तरीकों से काम करना बहुत मजेदार लगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन तरीकों ने कार्यशाला को अधिक रोचक और जानकारीपूर्ण बनाया।

किशोरों ने क्लिनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए, जिनमें सेवाओं के बेहतर प्रचार-प्रसार, निजता सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने और गैर-आलोचनात्मक स्थान बनाने पर जोर दिया गया, जहाँ युवा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर खुलेआम चर्चा कर सकें। प्रतिभागी अपने स्कूलों में अपने साथियों के साथ एकत्रित जानकारी साझा करने को लेकर भी उत्साहित थे। एक प्रतिभागी ने सुझाव दिया, हम अपनी असेंबली में 5 मिनट ले सकते हैं और किशोरों को स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी दे सकते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष इस बात को उजागर करते हैं कि उन स्वास्थ्य सेवाओं का आकार देने में किशोरों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है जो उनके लिए बनाई गई हैं। उनके विचार भविष्य में वास्तविक सुधार ला सकते हैं और यह दिखाते हैं कि जब युवाओं को भाग लेने का अवसर दिया जाता है, तो वे उन सेवाओं में सार्थक योगदान दे सकते हैं जिन पर वे निर्भर हैं।

संविधान के हर पहलू से रूबरू करवाता है 'संविधान कक्ष'

जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने देश के संविधान को पूरी तरह समर्पित एक संविधान कक्ष का निर्माण करवाया है

जयपुर। पीएमश्री विद्यालयों में किए जा रहे नवाचार अब प्रशंसा बटोर रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशन में विद्यालयों में नवाचार किए जा रहे हैं। नई सोच, नए प्रयास नए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा ही एक अनोखा उदाहरण पेश किया है जोधपुर जिले के बावड़ी कस्बे स्थित पीएम श्री

में योगदान देने वालों डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. बी आर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पं. जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कालाम आजाद, सचिदानंद सिन्हा, प्रो. के. टी. शाह, एच. वी. कामध्व, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी, वी.टी. कृष्णामाचारी, अल्लादी कृष्णा

- शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देशन में विद्यालयों में किए जा रहे विभिन्न नवाचार
- जोधपुर के बावड़ी कस्बे स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अनोखे नवाचार ने बटोरी प्रशंसा
- विद्यालय में बनाया गया है संविधान कक्ष, संविधान निर्माण से जुड़ी अद्भुत जानकारियों का किया गया है संकलन

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने। विद्यालय ने देश के संविधान को पूरी तरह समर्पित एक कक्ष का निर्माण करवाया है, जिसे संविधान कक्ष का नाम दिया गया है। यह कक्ष न केवल विद्यार्थियों को संविधान से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से रूबरू करा रहा है, बल्कि उनमें अपने देश के संविधान के प्रति आदर भाव भी बढ़ा रहा है।

सजा है महान विभूतियों की तस्वीरों से :-विद्यालय के संविधान कक्ष में संविधान से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जीवंत करने का प्रयास किया गया है। जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान की अनेक विशेषताओं को समावेशित करते हुए संविधान निर्माण

स्वामी अय्यर, गोपालस्वामी आर्यंगर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चौधरी रणबीर सिंह, एच.सी. मुखर्जी, फ्रैंक जे एथोनी, प्रो. सिम्बन लाल सक्सेना, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास, पुरुषोत्तम दास टंडन, जयपाल सिंह मुंडा, महावीर त्यागी, टी प्रकाशम, के संधान के हनुमंथैया के फोटो तैयार कर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्य नहीं होते हुए भी संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बी. ए. राव, नंदलाल बोस, एस एन मुखर्जी, एच वी आर आर्यंगर एवं प्रेम बिहारी नारायण रायजगदा के योगदान भी याद किया गया।

नारी शक्ति के योगदान को भी



किया रेखांकित :-संविधान कक्ष में नारी शक्ति के महती योगदान को भी याद किया गया है। संविधान सभा में 15 महिलाएँ सदस्य थीं, महिलाओं के संविधान निर्माण में योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से सभी 15 महिलाओं अम्मू स्वामीनाथन, दाक्षायणी वेलायुधन, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, मालती चौधरी, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, सरोजिनी नायडू, लीला रे, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, बेगम एजाज रसूल, ऐनी मस्करनीनी की तस्वीरें भी यहाँ लगाई गई हैं।

यहाँ संविधान की है विस्तृत जानकारी :-भारतीय संविधान से सम्बंधी महत्वपूर्ण तथ्यों में संविधान के भाग, अनुसूचियाँ, संविधान सभा के अधिवेशन, प्रारूप समिति, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियाँ, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, उद्देशिका मूल कर्तव्य, राजस्थान से संविधान सभा के सदस्य आदि के चार्ट तैयार कर लगाए गए हैं। इसके साथ ही संविधान निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण तिथियाँ जैसे 9 दिसम्बर 1946, 26 नवम्बर 1949, 24 जनवरी 1950 के दिन के कार्यों की भी प्रदर्शित किया गया है।

अब लगाए जाएंगे ऑडियो सिस्टम :-अपनी देखरेख में संविधान कक्ष को तैयार करने वाले राजनीति विज्ञान के स्कूल ख्याता सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित बताते हैं कि संविधान की मूल कॉपी पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सभी सदस्यों के हस्ताक्षर, संविधान सभा से संबंधित चित्र और संविधान सभा में विभिन्न सदस्यों के कथन आदि के पोस्टर लगाकर संविधान कक्ष को जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अगले चरण में संविधान सभा में कैमरे, संविधान कक्ष में मॉडिंग लगाना, संविधान कक्ष में संविधान की मूल कॉपी रखने का कार्य किया जायेगा। साथ ही ऑडियो सिस्टम भी लगाया जायेगा ताकि संविधान व संविधान कक्ष से संबंधित जानकारी विद्यार्थियों, अभिभावकों के साथ साझा की जा सके।

शुरुआत से ही बच्चे जानें अपना संविधान :- संविधान कक्ष जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री दिनेश गहलोत की देखरेख में तैयार हुआ है। उनका कहना है कि संविधान कक्ष बनाने के पीछे लक्ष्य यह था कि नई पीढ़ी शुरुआत से ही संविधान के बारे में जानें। यह किन परिस्थितियों में तैयार हुआ, किन-किन लोगों की भागीदारी रही जैसी बातें उन्हें पता चलें। पीएम श्री विद्यालयों में नागरिक सहभागिता के तहत यह किया गया है। यह कदम बेहद कारगर साबित हो रहा है। प्रधानाचार्य अंजना दवे सहित विद्यालय परिवार व भामाशाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

राशिफल शुक्रवार 7 मार्च, 2025



पंडित अनिल शर्मा

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2081, मृगशिरा नक्षत्र रात्रि 11:32 तक, प्रीति योग सायं 6:14 तक, बव करण प्रातः 9:19 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:45 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरु-वृष, शुक-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज रवियोग रात्रि 11:32 से आरम्भ होगा। आज दुर्गाष्टमी है। आज से होलाष्टक आरम्भ होगा और अष्टानिका महापर्व आरम्भ (जैन) होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:16 तक, लाभ-अमृत 8:16 से 11:11 तक, शुभ 12:38 से 2:05 तक, चर 5:00 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:49, सूर्यास्त 6:27

मेघ
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बरने लगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में/आय में वृद्धि होगी। परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मिथुन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। दिन के मध्य-पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात अनावश्यक धन खर्च हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों में वृद्धि होगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। अटके हुए कार्य बरने लगे। दिन के मध्य-पश्चात आर्थिक मामलों में उचित सफलता मिलेगी।

कन्या
आज शुभ-मांगलिक कार्यों के स्थान को यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बरने लगे।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्य-पश्चात अटक हुए कार्य बरने लगे।

वृश्चिक
अपने अति आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है। बरने कार्य बिगड़ सकते हैं।

धनु
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटक हुए कार्य बरने लगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
घर-परिवार में चल रहे आपसी विवाद समाप्त होंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ
घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में अतिथियों का आगमन होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन
परिवार में शुभ संदेश प्राप्त होगा। परिवारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी।

आज हम फल सब्जियों, गेहूँ, दूध, घी सबमें जहर खा रहे हैं : हरीश चौधरी

विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग की मांगों पर बहस में भाग लिया

जयपुर। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पीने के पानी की गुणवत्ता पर मेडिकल विभाग को रिपोर्ट स्पष्ट करनी चाहिए। पानी में फ्लोराइड जैसे तत्व सबसे ज्यादा हैं। सरकार को इसमें सम्बंधित विभागों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। थार के अंदर पानी के टांक बने हुए हैं, उनमें पानी की गुणवत्ता है। आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

■ 'जहर मिलाने वालों के लिए हमने बड़े कमजोर नियम बना रखे हैं, ऊपर से दोषियों को बचा रहे हैं'

होनी चाहिए। मिलावटी खाने के बारे में जनता को सही जानकारी देने की हमारी जिम्मेदारी है। आज हम फल सब्जियों,

गेहूँ, दूध, घी सबमें जहर खा रहे हैं। सदन कोई कानून नियम नहीं बना रही। उन्होंने कहा कि गोमाता की जय तो बोलते हैं, लेकिन यह नहीं देख रहे कि बाजार में मिल रहे गाय के घी में कितनी मिलावट आ रही है। गाय के आहार में मिल रहे पेस्टिडाइड्स से हमें दूध में जहर मिल रहा है। हरीश चौधरी ने कहा कि जहर मिलाने वालों के लिए हमने बड़े कमजोर नियम बना रखे हैं। ऊपर से दोषियों को बचा रहे हैं। हमें जांच लैब

की कमी पर बात करनी चाहिए। एसएमएस अस्पताल में 15 हजार की ओपीडी होना चिंताजनक है। इलाज का विकेंद्रीकरण करना होगा। हमें किसी देश के मॉडल अपनाने की जगह राजस्थान की परिस्थितियों के हिसाब से मॉडल बनाना चाहिए। मेडिकल सेंट्रलाइज्ड करने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को जयपुर आना पड़ता है और शहरी लोगों को निजी अस्पतालों में जाना पड़ता है। कोरोना से मेडिकल अधिकारियों ने नहीं नर्सिंग स्टाफ ने लड़ाई लड़ी। उन्हें सल्यूट करता हूँ। आज उन्हीं लोगों की भर्ती नहीं हो रही। बायतु उपजिला अस्पताल के अंदर 38 स्वीकृत पदों में सिर्फ 14 पद भरे हैं। जेनेरेटिक दवाइयों को बढ़ावा देने की साथ एंटीबायोटिक दवाइयों के दुष्परिणाम के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। स्टेरॉइड के कारण बहुत मौतें हुईं। हमें कोई नीति बनानी पड़ेगी। चिरंजीवी योजना के माध्यम से लोगों को 25 लाख का इलाज मिल रहा था। आज नाम बदल दिया, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। इंड्योरेंस कंपनी की वजह से पैसा अटकने के कारण लोग अस्पतालों में क्लेम के लिए धक्के खा रहे हैं। सरकार की क्लेम दिलाए की प्राथमिकता नहीं है। आरजीएचएस के भुगतान के लिए मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि इसका पैसा टाइम पर नहीं मिलता। टोटल फर्टिलिटी टेस्ट को भी समझने की आज जरूरत है।

आपकी कृपा से विधायक नहीं हूँ : कुलदीप धनकड़

जयपुर। विधानसभा में अनुदान मांगों पर बोलने वालों की लिस्ट से नाम काटे जाने के मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक कुलदीप धनखड़ और सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। दोपहर में लंच टेबल पर दोनों ने एक-दूसरे को जमकर खरी-खोटी सुनाई। इस दौरान कई विधायक भी मौजूद थे, सीनियर नेताओं ने बीच-बचाव कर मामला शांत करवाया। धनखड़ स्वास्थ्य की अनुदान मांगों पर बोलना सचेतक थे, लेकिन सचेतक ने उनका नाम नहीं लिखा, इस मुद्दे पर बात

■ मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग और भाजपा विधायक धनकड़ के बीच हुई नोक-झोंक

इतनी बढ़ी कि कई विधायकों की मौजूदगी में लंच के दौरान भिड़ गए। धनखड़ ने गर्ग से नाराजगी जताते हुए कहा कि टारगेट बनाकर मेरा नाम हटाया गया। इस पर गर्ग ने और भी 10 विधायकों के नाम हटाने का तर्क दिया।

इस बीच दोनों के बीच बहस बढ़ गई, गर्ग ने गुस्से में यहाँ तक कह दिया कि अपने दिमाग से गंदगी को निकाल दो। बदले में धनखड़ ने भी कह दिया को गंदगी आपके दिमाग में है। गर्ग इस पर गुस्सा हो गए, और कहा कि आपने तो मुख्यमंत्री तक शिकायत कर दी, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। धनखड़ ने फिर पलटवार किया और कहा कि मैं आपकी कृपा से विधायक नहीं हूँ। इस बीच वरिष्ठ विधायकों ने बीच-बचाव किया और दोनों को शांत करवाया।

दिया कुमारी को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवॉर्ड

जयपुर। पॅसिफिक एशिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी को वीमन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान आईटीबी बर्लिन, जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉ. एलन सेंटएन्ज द्वारा दिया गया। उप मुख्यमंत्री की ओर से पर्यटन विभाग के अधिकारी, अपर निदेशक आनंद त्रिपाठी, उप निदेशक पर्यटन उपेन्द्र सिंह शेखावत ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया।

गहलोत व डोटासरा विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को कलंकित कर रहे हैं : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के शुभारंभ को लेकर दिये गये बयान पर जोधपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी सरकार के समय होने वाले निर्माण कार्य प्रदेश की जनता के टेक्स से होते हैं। गत सरकार में कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान को संचालित करने वाली कार्यकारी संस्था का चयन नहीं हुआ था लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस संस्था के चयन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित विधानसभा के सदस्यों को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब के प्रवेश के समय आमंत्रित किया जाना पूरी तरह

न्यायसंगत और विधिसम्मत है। राठौड़ ने कहा कि जिस प्रकार घर में प्रवेश करते समय परिवार के सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है उसी तरह कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का संस्थान करने वाली संस्था के चयन के उपरांत क्लब के विधिवत कार्यशील होने के महत्वपूर्ण अवसर पर सदस्यों को आमंत्रित करना गतवत कैसे हो सकता है? दुर्भाग्य है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को कलंकित करने का काम कर रहे हैं और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए विधानसभा अध्यक्ष का अपमान करने में जुटे हैं। राठौड़ ने कहा

कि कांग्रेस नेताओं द्वारा बार-बार विधानसभा अध्यक्ष को अपमानित करना ना केवल संसदीय परंपराओं को कमजोर करने का प्रयास है बल्कि उनकी संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाता है। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के प्रति निम्न स्तर के शब्दों का प्रयोग करना, निलंबित होने पर 7 दिन तक बेवजह गतिरोध बनाये रखना तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के माफी मांगने पर गतिरोध समाप्त होने के बाद भी सदन से लगातार अनुपस्थित रहना यह दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी में गहलोत बनाम पालटल गुट के अलावा अब नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के नये गुट में अंतर्कलह प्रारंभ हो गई है।

रंगाई-छपाई की 848 इकाइयों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पर रोक

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सांगानेर की 848 रंगाई-छपाई इकाइयों से निकले अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए बनाए सीईटीपी की निर्माण राशि व इससे जुड़ी करीब 96 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में सांगानेर कपाड़ रंगाई छपाई एसोसिएशन के निदेशकों, पदाधिकारियों व सदस्यों के स्वामित्व वाली संपत्तियों को कुर्क करने के संबंध में कॉर्पोरेट कोर्ट के गत 14 फरवरी के आदेश की क्रियाविति पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस अनीशा झिंगन व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश गुरुवार को राज्य सरकार की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

अदालत ने कहा कि पहले याचिका की मटेनेबिलिटी पर सुनवाई की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से महाविधायक राजेन्द्र प्रसाद ने कॉर्पोरेट कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 13 के तहत अपील दायर कर कहा कि कॉर्पोरेट कोर्ट का आदेश पूरी तरह से विधि के प्रावधानों के खिलाफ है। प्रार्थी फर्म अपने व्यावसायिक हिाइट्स के लिए कोर्ट के डिक्ट्री आदेशों का क्रियान्वयन करवाना चाहता है। इसके जवाब में दावाकर्ता फर्म मैसर्स एंडवैट एंवायरकेयर टेक्नोलॉजीज ने कहा कि राज्य सरकार की अपील सुनवाई के लिए मटेनेबल नहीं है।

कैंसर जांच व जागरूकता अभियान

जयपुर। रघुकुल ट्रस्ट, भावान महावीर कैंसर हॉस्पिटल और कैंसर केयर की संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को जयसिंह पुरा रोड पर कैंसर जांच एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। हवा महल क्षेत्र से एमएलए महाराज बालमुकुंद आचार्य की सानिध्य में, रोहित पब्लिक स्कूल के सहयोग से स्कूल परिसर में आयोजित इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया। अभियान के उद्घाटन समारोह में पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने कैंसर जांच के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर समाजसेवी व कैंसर विजेता साजना गर्ग ने जनता को प्रोत्साहित करके कहा की अर्ली डिटेक्शन कैंसर से बचने का मूल मंत्र है। कैंसर स्त्रीोंग के माध्यम से कैंसर रोगी अपने आप को एवं अपने परिवार को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक त्रासदी से बचा सकता है।

सहारा प्राइम सिटी के मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के आदेश

जयपुर। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा सहारा प्राइम सिटी के विरुद्ध अवमानना कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की हर संभव गिरफ्तारी करने के आदेश दिए हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा दो दिनों में अलग-अलग कुल 67 अवमानना प्रकरणों की सुनवाई करते हुए पुलिस के विशेष बल द्वारा कई कार्रवाई का अवलोकन किया। पुलिस द्वारा बताया गया कि नोटिस तामील नहीं हो पा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष देवेश कच्छवाहा, सदस्य न्यायिक निर्मल सिंह मेहतावाल, सदस्य लियकात अली ने आदेश दिया कि

आयोग द्वारा लंबे समय से वारंट बार-बार जारी किए जा रहे हैं। विशेष पुलिस बल का गठन भी किया गया है। आयोग द्वारा अपने आदेश में कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात हो रहा है कि वारंटों का अनबुझकर प्रकरणों में पूर्व में जारी जमानती वारंट की तरह गिरफ्तारी वारंट की भी तमिल ले जाते हैं, और फिक्ट भविष्य में वारंटों की तमिल निष्पत्ती क्रम में होने की संभावना नहीं है। अतः प्रकरण के शेष अप्रार्थी, अभियुक्त के विरुद्ध वारंट पुनः जारी कर विशेष पुलिस दल को सुपुर्द किए जाएं और गिरफ्तारी वारंट पर पूर्व की तरह शर्त लिखी जावे।

भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में सशक्त अनुसंधान एवं प्रभावी अभियोजन महत्वपूर्ण : डॉ. मेहरड़ा

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान द्वारा गुरुवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में "इन्वेस्टिगेशन ऑफ डी ए केसेस : ए क्रेपेहेंसिव एप्रोच इन दी लाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि महानिदेशक, एसीबी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा और विशिष्ट अतिथि डी.सी. जैन, सेवानिवृत्त डीजी द्वारा किया गया। महानिदेशक एसीबी मेहरड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आय से अधिक सम्पत्ति मामलों पर विस्तार से चर्चा कर डी ए केसेस की जांच को नए आपराधिक कानूनों के तहत अधिक प्रभावी बनाना और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करना है। महानिदेशक ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं ब्यूरो के अधिकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर नये कानून पर एक साथ चर्चा करने से



भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से गुरुवार को जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में "इन्वेस्टिगेशन ऑफ डी ए केसेस : ए क्रेपेहेंसिव एप्रोच इन दी लाइट ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्रभावी ज्ञानवर्धन का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में आपसी समन्वय की भावना के साथ मजबूत अनुसंधान करने में भी सहायता

मिलेगी। उन्होंने इस कार्यशाला को अनुसंधान अधिकारियों और अभियोजन अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक

महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध जोरि टॉलरेंस नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता

'गौशालाओं को देय अनुदान राशि में हो रही निरंतर वृद्धि'

जयपुर। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को विधानसभा में राज्य सरकार को गौशालाओं के रख-रखाव के लिए संवेदनशील बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बजट वर्ष 2024-25 में गौशालाओं को देय अनुदान सहायता राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि की गई थी और अब बजट वर्ष 2025-26 में भी 15 प्रतिशत की वृद्धि के लिए घोषणा की गई है। कुमावत प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 4 हजार 140 गौशालाएं संचालित हैं। इनमें से 3 हजार 43 गौशालाएं इस वर्ष अनुदान सहायता राशि के लिए पात्र हैं।



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गईं। मालवीय नगर में सेक्टर 1 के गर्ल्स स्कूल में कक्षा 10 का एग्जाम देने जाते विद्यार्थी।

नागपुर में जल्द शुरू होगा 'पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क'

जयपुर। नागपुर के मिहान (नागपुर में मल्टी-मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट) क्षेत्र में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क 9 मार्च को परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। मिहान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु भूमि पूजन का कार्य सितम्बर 2016 में किया गया था।

नागपुर में स्थापित होने वाला पतंजलि का यह फूट्स एण्ड वैजेटेबल्स प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें सिसटरस तथा ट्रापिकल फल व सब्जियों को प्रोसेस करके जूस, जूस कन्संट्रेट, पल्प, पेस्ट व च्यूरी का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा

■ लगभग 700 करोड़ किया जा चुका है निवेश, करीब 1500 करोड़ निवेश करने की योजना

की विदित है, नागपुर पूरे विश्व में अर्रिज सिटी के नाम से विख्यात है, यहाँ सिसटरस फूट्स जैसे संतरा, कौनू, मौसम्मी, नींबू इत्यादि की बहुलता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पतंजलि ने सिसटरस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया है। इस सिसटरस प्रोसेसिंग प्लांट में प्रतिदिन 800 टन फूट

प्रोसेस करके प्रोजन जूस कन्संट्रेट बना सकते हैं। यह जूस 100 प्रतिशत प्राकृतिक है तथा इसमें किसी भी प्रकार के फ्रिजवैटिंग या शुगर का प्रयोग नहीं किया जाता।

इसके साथ-साथ ट्रापिकल फूट्स का भी प्रसंस्करण किया जाता है जिसमें अंबेला प्रतिदिन 600 टन, आम प्रतिदिन 400 टन, अमरूद प्रतिदिन 200 टन, पपीता प्रतिदिन 200 टन, सेव प्रतिदिन 200 टन, अनार प्रतिदिन 200 टन, स्ट्रूबेरी प्रतिदिन 200 टन, प्लम प्रतिदिन 200 टन, नाशपाती प्रतिदिन 200 टन, टमाटर प्रतिदिन

400 टन, लौकी प्रतिदिन 400 टन, करेला प्रतिदिन 400 टन, गाजर 160 टन, एलोविरा 100 टन प्रतिदिन टन प्रोसेस करके वैश्विक विनिर्देश के अनुसार जूस, जूस कन्संट्रेट, पल्प, पेस्ट व च्यूरी का उत्पादन कर सकते हैं। फूट से सीधे प्रोसेसिंग की इस प्रक्रिया को प्राइमरी प्रोसेसिंग कहते हैं।

इस प्लांट में अभी तक लगभग 700 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। इस पूरी कार्य योजना में लगभग 1500 करोड़ निवेश की योजना है। इस प्लांट के स्थापित होने से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित होगा।

श्रीजी का फाग उत्सव मनाया

जयपुर। श्रीजी का फाग उत्सव गुरुदेव गोस्वामी प्रेमकुमार महाराज, गोस्वामी हितेंद्र कुमार, गोस्वामी प्रियांश (छोटी सरकार श्रीधाम वृंदावन) के सानिध्य में मनाया गया। रसिक जन होली धमाल के पदों पर नृत्य कर बहुत आनंद लिया। फागोत्सव जवाहर सर्किल स्थित गोकुल वाटिका पर रविवार को फूलों की होली एवं भजन संध्या का आयोजन हुआ। आयोजक सुरेश टांक, राजेन्द्र, विष्णु टांक ने अतिथियों का दुग्धु ओढ़ाकर और फूल बरसाकर सम्मान किया। विष्णु टांक ने बताया कि हर वर्ष फाग श्याम भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। फूलों की होली खेली जाती है। राधाकृष्ण स्वरूप झांकी सजाई गई श्याम जी का फूलों की झांकी से श्रृंगार किया। श्याम रसिया, फागण आयो रंग रसिया रंग रसिया

आर.यू.एच.एस. का कुलपति महाराष्ट्र के फार्मासिस्ट को बना दिया : बराला

'क्या राजस्थान का एक भी डॉक्टर इस पद के लाइक नहीं था?'

जयपुर। कांग्रेस विधायक शिखा मील बराला ने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में गैर डॉक्टर को कुलपति बनाए जाने पर सवाल उठाए। स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान शिखा मील बराला ने कहा कि आरयूएचएस में एक नई पची के स्वास्थ्य विभाग के गलियारों में बड़े चर्चे हैं। आरयूएचएस वीसी पद पर महाराष्ट्र के रहने वाले फार्मासिस्ट को लगाया गया है, वह राजस्थान के सभी वरिष्ठ और योग्य अनुभवी डॉक्टर के पर एक सवालिया निशान है। ये वहाँ डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपने करियर में हजारों स्पेशलिस्ट तैयार

कर दिए। क्या राजस्थान का एक भी डॉक्टर इस पद के लाइक नहीं था? बराला ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन की स्थिति बहुत चिंताजनक है। नए मेडिकल कॉलेजों में यू-ट्यूब से और बिना फैकल्टी पढ़ाई हो रही है और यह डॉक्टर हमारा इलाज करेंगे। इंडियन मेडिकल काउंसिल (आईएमसी) 8वीं-10वीं पास लोगों को फर्जी डिग्री देती है, ऐसे डॉक्टर फिर फील्ड में जाकर इलाज करेंगे तो मौतें होंगी, वो सरकार के खाते में लिखी जाएगी। राजस्थान में फ्रिजिडोथेरेपी कार्डिसल नहीं है, इसकी स्थापना होनी चाहिए।

राष्ट्रीय लोक अदालत 8 को

जयपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशन में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों एवं अन्य प्रशासनिक प्राधिकरणों में आयोजित होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में इस लोक अदालत का शुभारंभ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस श्री चंद्रशेखर तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में प्रातः 10 बजे किया जाएगा।

राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट : पटेल

जयपुर। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। पटेल प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे 15वीं विधानसभा के अष्ठम सत्र में 21 मार्च 2023 को विधानसभा द्वारा पारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी तक प्राप्त

■ विधायक अमीन कागजी के प्रश्न पर विधि मंत्री जोगराम पटेल ने जवाब दिया

नहीं हुई है। इससे पहले विधायक अमीन कागजी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 31 जिला एवं सेशन न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इनमें वर्तमान में 33 हेड कॉन्स्टेबल तथा 131 कॉन्स्टेबल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं।

कांस्टीट्यूशन क्लब के उद्घाटन का कांग्रेस बहिष्कार करेगी

जयपुर। कांस्टीट्यूशन क्लब को लेकर प्रदेश में सियासी पारा गरम हो गया है। कांग्रेस ने 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन का बहिष्कार का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि जिसका उद्घाटन हो चुका, उसका फिर से उद्घाटन क्यों? हम बहिष्कार करते हैं।

कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी सरकार ने कांस्टीट्यूशन क्लब न केवल बना दिया था, बल्कि उसकी उद्घाटन भी कर दिया था। बावजूद इसके, अब इसका फिर से उद्घाटन किया जा रहा है। 8 मार्च को होने वाले उद्घाटन समारोह में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। हम इस समारोह का बहिष्कार करते हैं। जूली ने कहा कि उद्घाटन हो चुका है, शुभारंभ के नाम पर वापस इसका उद्घाटन करना चाह रहे हैं। यह गलत परंपरा है। इस गलत परंपरा का हमारी पूरी पार्टी, पूरा विधायक दल इसका बहिष्कार

■ कांग्रेस बोली, "दोबारा उद्घाटन क्यों? हम बहिष्कार करते हैं"

करेगा। इस प्रकार से गलत परंपरा में विपक्ष शामिल नहीं होगा। जूली ने कहा कि कांस्टीट्यूशन क्लब में पट्टिका लगी हुई है। क्लब का उद्घाटन पहले हो चुका है। इस पर पुनर्विचार किया जाए।

भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ पट्टियां लगाने का काम किया। विधायक आवास में डेढ़ साल नहीं हुआ, दरारें आ गईं, टाइल्स उखड़ गईं, छत से पानी टपकने लग गया। कांग्रेस ने ऐसे भ्रष्टाचार के नमूने जगह-जगह खड़े कर दिए। कांग्रेस ने सिर्फ सिलापट्टी का लगाया और लगाते जाने का ही काम किया। इसलिए, कांग्रेस के आरोप यह सब फिजूल की बातें हैं।

मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में की जायेगी सख्त कार्रवाई : बेदम

जयपुर। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेदम ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री रोकने के लिए राज्य सरकार सजग है और अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत एवं तस्करी में लिप्त की शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। बेदम प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।

उन्होंने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के पूरक प्रश्न 'क्या मादक पदार्थ तस्करी मामलों में पुलिस की गठजोड़ की कोई कार्ययोजना है' पर कहा कि अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी शिकायत आने पर कठोर कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और तस्करी रोकने के लिए सजगता से कार्रवाई की जा रही है।

सांसद मन्नालाल रावत ने मध्य प्रदेश के मजदूरों की व्यथा सुनी

रावत ने अधिकारियों को मजदूरों का भुगतान दिलवाने के निर्देश दिए

उदयपुर, (निसं)। मध्यप्रदेश से आए मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा भुगतान नहीं मिलने और कलेक्ट्री के बाहर पुलिस द्वारा उनको खदेड़ने के मामले में संज्ञान लेते हुए सांसद मन्नालाल रावत गुरुवार को सभी मजदूरों से मिले और उनकी बात सुनी। बाद में उन्होंने इस मामले में वन विभाग के रेंजर से लेकर डीएफओ तक के अधिकारियों से मौके पर ही बात कर जल्दी मजदूरों को उनका वाजिब भुगतान दिलाने के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार सांसद रावत दोपहर में गांधी ग्राउंड पहुंचे जहां बाहर इन मजदूरों से बुधवार से डेरा डाल रखा है। करीब डेढ़ सौ मजदूरों में कई महिलाएं और बच्चे भी हैं, जिनसे सांसद ने सबसे पहले उनके खाने और रहने की व्यवस्था के बारे में पूछा। सारे लोगों को निगम के रैन बसेरा के हॉल में एकत्र कर उनसे पूरे मामले के बारे में पूछा। मजदूरों की ओर से लालजी ने बताया कि ठेकेदार ने उनको 70 रूपए प्रति खड्डा खोदने तथा नाडी बनाने के लिए बुलवाया।



सांसद मन्नालाल रावत ने मजदूरों से बातचीत की।

इस पर करीब 186 लोग पहुंचे और परसाद व अन्य जगहों पर खड्डों की खुदाई व नाडी बनाने का काम किया। जब भुगतान का समय आया तो ठेकेदार बदल गया और उसने 25 रूपए प्रति खड्डे के हिसाब से ही भुगतान की बात कही। सांसद ने जब मजदूरों

ने एग्रीमेंट लिखित में होने की बात पूछी तो उन्होंने मना कर दिया। सांसद ने मजदूरों के सामने ही मामले से जुड़े रेंजर से फोन पर बात की और बाद में डीएफओ मुकेश सैनी से भी मामले की जानकारी लेकर मामले को जल्दी निबटार कर मजदूरों को भुगतान दिलाने

के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि डेढ़ सौ से ज्यादा मजदूर चार दिन से इधर-उधर भटक रहे हैं। उनके रहने खाने की भी दिक्कत है। महिलाएं और बच्चे भी हैं इसलिए इनका वाजिब भुगतान दिलवाकर इनके गांव रवाना करें। मजदूरों की मांग पर सांसद रावत

■ **मजदूरों को लेकर डीएफओ ने कहा कि सबको नियमानुसार खाते में भुगतान मिलेगा**

कुछ मजदूरों को लेकर डीएफओ मुकेश सैनी के चेतक सर्कल स्थित ऑफिस भी पहुंचे। वहां मजदूरों व डीएफओ की आमने-सामने बात करवाई। डीएफओ ने कहा कि सरकारी नियमानुसार जो भी भुगतान बन रहा है वो उनको दिलवा देंगे और नगद भुगतान की बजाए प्रत्येक मजदूर के खाते में भुगतान करवाया जाएगा ताकि बाद में कोई विवाद नहीं हो। करीब दो घंटे तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत करवाने के बाद सांसद ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनका भुगतान हो जाएगा। साथ ही खदेड़ने वाले पुलिसकर्मियों को लेकर वे पुलिस अधिकारियों से बात करेंगे। बीमार महिलाओं और बच्चों के इलाज के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए।

वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं : शेखावत

जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत गुरुवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के दक्षिण भारत में परिसीमन के बाद कम होने वाली सीटों को लेकर दिये बयान पर कहा कि वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका उनका सारा विषय एंग्रेशन और वहम के बेस है। कुछ लोग वहम के कारण से ऐसा करते हैं। कुछ लोग इस तरह के वहां से इस तरह का पॉलिटिकल लाभ पाने की कोशिश करते हैं। अब देखने का विषय की स्टालिन कौन से ब्रैकेट में खड़े हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व में बुधवार को जनगणना आधारित परिसीमन और ट्रायल लैंग्वेज वार पर सर्वदलीय बैठक भी हुई। उन्होंने कहा कि यदि संसद में सीटें बढ़ती है तो 1971 की जनगणना को आधार बनाना चाहिए। शेखावत ने बीकानेर जिले के करणी माता मंदिर में प्रसाद योजना के तहत 22.5 करोड़ रूपए की लागत से करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी।

■ **तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के दक्षिण भारत में परिसीमन के बाद कम होने वाली सीटों को लेकर दिये बयान पर बात की**

■ **शेखावत ने करणी माता मंदिर में करवाए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर जानकारी दी**

कहा पर्यटन क्षेत्रों के विकास और भारत में धार्मिक पर्यटन के महत्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसाद योजना को लागू किया था। करणी माता मंदिर उनके ही नहीं देशवासियों के लिए आस्था का विषय है। वहां दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव में सुधार किया जाए, उनके लिए आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा सके। इसके लिए राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट

प्रस्तावित किया था। इसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने इसको लेकर मंत्रालय से आह्वान किया था। उनके आग्रह पर स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे करणी माता मंदिर में विकास कार्य करवाए जाएंगे। राजस्थान सरकार और भी मंदिरों को लेकर प्रस्ताव भेजेगी तो आने वाले वर्षों में और प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के बेटे की शादी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस तरह की शादियों से शहर और अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ होता है। निश्चित रूप से इस तरह की बड़ी शादियों से राजस्थान की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। महाराष्ट्र के सपा नेता अब्बू आजमी के बयान को लेकर कहा कि उनके बयान का उचित जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में दे दिया है।

सपा नेता अब्बू आजमी ने 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में कहा था कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं मैं उससे क्रूर शासक नहीं मानता। इस बयान को लेकर बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया था।

नांदवेल सरपंच पर फायरिंग करने के आरोपी को गिरफ्तार किया

■ **ग्रॉपर्टी विवाद के चलते सरपंच पर फायरिंग की थी, फायरिंग का आरोपी पेशे से वकील बताया जा रहा है**

उदयपुर, (निसं)। नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के आरोपी को डबोक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि नांदवेल सरपंच देवीलाल डांगी पर फायरिंग करने के आरोपी पीयूष राजपूत पिता मिथलेश निवासी बड़गांव को डबोक थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पीयूष राजपूत पेशे से वकील हैं और उदयपुर कोर्ट में बीते सात से वकालत कर रहा है। ग्रॉपर्टी विवाद के चलते इसने अपने साथी के साथ मिलकर सरपंच पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। सरपंच मावली विधायक पुष्कर

डांगी का भांजा है। आरोपी पीयूष ने पुलिस पृष्ठताछ में बताया कि उसके पिता मिथलेश ने सुरेश सालवी नाम के व्यक्ति से जमीन लेने की बात पक्की की थी। लेकिन नांदवेल सरपंच ने भी उसी जमीन को लेने के लिए सुरेश सालवी से सम्पर्क किया। सरपंच ने हमें जमीन नहीं लेने दी और खुद का लिखित सौदा कर लिया। पीयूष ने पुलिस को बताया कि इस बात से पिताजी परेशान थे जिसे लेकर उसने सरपंच पर फायरिंग की योजना बनाई। इसके लिए उसने किसी से देसी कट्टा खरीदा था। मामले में इसका

दूसरा साथी फरार है जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान की थी। आरोपी पीयूष ने घटना को अंजाम देने से पहले अपना मोबाइल किसी परिचित के होटल पर रख दिया था, ताकि पुलिस मोबाइल लोकेशन से उसे ट्रैक नहीं कर पाए। उल्लेखनीय है कि मंगलवार रात करीब 10 बजे जब सरपंच देवीलाल डांगी कार से अपने घर पहुंचे थे। जैसे ही कार से उतरकर बाहर निकले, तभी उनके पर फायरिंग कर दी। गोली उनके जांघ पर लगकर आर-पार निकल गई। उनके

चिल्लाने पर बदमाश वहां से भाग गए। उनकी आवाज सुनकर परियन घर से बाहर आए और घायल सरपंच को हॉस्पिटल लेकर गए।

सरपंच का कहना है कि वे जब घर पहुंचे थे तब दो युवक पास की टंकी पर पानी पी रहे थे मुझे घटना का अंदाजा नहीं था। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने फायरिंग कर दी। थानाधिकारी हुकम सिंह ने बताया कि घटना में लिफ्ट दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने देसी कट्टा कहां और किससे खरीदा, इसका पता लगाया जाएगा। साथ ही जमीन बेचने वाले सुरेश सालवी की इस मामले में क्या भूमिका रही है इस संबंध में सुरेश से भी पृष्ठताछ की जाएगी।

18 लाख की शराब तस्करी के मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

पांच हजार के इनामी सहित दो जनों को गिरफ्तार किया

■ **पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर से पंजाब, चंडीगढ़ और राजस्थान निर्मित अवैध शराब बरामद की थी**

गया था। कंटेनर की तलाशी में 18 लाख रूपए की अवैध शराब मिली थी, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब के साथ ही राजस्थान निर्मित शराब के 249 कार्टन शराब भर रहे थे।

पुलिस ने मौके से हेमासिंह उर्फ हेमू रावत पुत्र मोतीसिंह रावत निवासी गुडा जिला ब्यावर को गिरफ्तार किया

था। पुलिस मामले में शराब तस्करी की कड़ी जोड़ रही थी। थानाधिकारी ने बताया कि शराब को मुख्य तस्करी दुर्गेश उर्फ दुर्गासिंह पुत्र लालसिंह रावत राजपूत निवासी बड़ी समेल जिला ब्यावर और अशोक पुत्र फतेहसिंह रावत राजपूत निवासी मोडा काकर जिला राजसमंद को नामजद कर तलाश

की जा रही थी, मुख्य तस्करी दुर्गेश उर्फ दुर्गासिंह टॉप 10 आरोपी होने से उस पर पांच हजार रूपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस को दोनों तस्करी के अजमेर में होने का पता लगा, जिस पर पुलिस टीम अजमेर पहुंची, जहां से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस शराब तस्करी को लेकर दोनों आरोपियों से पृष्ठताछ कर रही है। वहीं गुजरात में शराब तस्करी से भी तार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

‘दुराचरण व लापरवाही के आरोपों से घिरे टीचर्स की बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी नहीं लगेगी’

■ **उप निदेशक (माध्यमिक) रमेश कुमार हर्ष ने आदेश जारी किए**

बीकानेर, (निसं)। प्रदेश में गुरुवार से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं। इन परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दुराचरण और लापरवाही के आरोपों से घिरे टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। उप निदेशक (माध्यमिक) रमेश कुमार हर्ष ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।

एग्जाम शुरू होने से ठीक एक दिन पहले जारी इस आदेश में कहा गया है कि ब्लैक लिस्टेड कार्मिक और जिन कार्मिकों पर विभागीय जांच प्रस्तावित है

और दुराचरण और परीक्षा में लापरवाही के दोषी हैं, उन्हें बोर्ड परीक्षा के सभी कामों से दूर रखा जाएगा। अगर कोई जिला शिक्षा अधिकारी या केंद्र अधीक्षक ऐसे कार्मिकों की ड्यूटी लगाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप निदेशक हर्ष ने आदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान स्कूल की अन्य परीक्षाओं के बाधित नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। जिन स्कूलों से टीचर की

वीक्षक के रूप में ड्यूटी लग रही है, वहां कुछ टीचर्स को पढ़ाने के लिए ड्यूटी से मुक्त रखना पड़ेगा। वीक्षक ड्यूटी को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के निर्देशों की पालना करने के आदेश दिए गए हैं। एग्जाम के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही करने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया गया है।

शातिर नकबजन गिरफ्तार

जयपुर। करघनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात करने वाले एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि उसके खिलाफ करघनी थाना क्षेत्र एवं आसपास के इलाकों में दर्ज दो से अधिक चोरी की वारदातों का खुलासा

हुआ है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि करघनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की वारदात करने वाले एक शातिर नकबजन अशोक नायक उर्फ बाबू उर्फ गिण्डिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पृष्ठताछ कर रही है।

स्मैक सहित एक गिरफ्तार

टोंक, (निसं)। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन जिले में चलाये जा रहे अभियान अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के तहत वृत्ताधिकारी मालपुरा आशीष प्रजापत के सुपरविजन में थानाधिकारी टोडारामसिंह हरिराम द्वारा गठित टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु कस्बा टोडारामसिंह में कार्यवाही करते हुए आरोपी राजेन्द्र उर्फ राज पुत्र महावीर निवासी वार्ड नं. 06 कस्बा टोडारामसिंह अवैध मादक पदार्थ 6.75 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

दो समुदायों में कहासुनी के बाद झगड़ा, आधा दर्जन लोग घायल

पुलिस ने मामला दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया

चाकसू, (निसं)। चाकसू कस्बे के वार्ड नंबर पांच स्थित दरियों के मोहल्ले में बीती देर रात दो समुदायों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें

■ **समुदाय विशेष के युवकों पर गाली-गलौज करने व हमला करने का आरोप**

उपचार के लिए स्थानीय उप जिला अस्पताल ले जाया गया। वहां से दो गंभीर घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर चाकसू व शिवदासपुर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया।

जानकारी के मुताबिक, समुदाय विशेष के कुछ युवकों द्वारा मोहल्ले में उत्पात मचाने पर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बढ़ते-बढ़ते झगड़े में बदल गई। विवाद बढ़ने पर समुदाय विशेष के 40-50 लोगों वहां पहुंचे और दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट शुरू



पुलिस ने मौके पर जाकर लोगों से समझाइस की।

कर दी। झगड़े में एक पक्ष ने आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया। झगड़े के बाद समुदाय विशेष के युवक वहां से फरार हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती

कराया, जहां से 2 जनों को गंभीर हालत में रेफर किया। देर रात तक पीड़ित पक्ष के लोग मौके पर जमा रहे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस के मुताबिक, इलाके में फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पीड़ित पक्ष के कैलाश गुर्जर ने 4 नामजद समेत 40-50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

सूने मकानों में चोरी करने के मामले में युवक गिरफ्तार

सांभरझील, (निसं)। सूने मकानों में चोरी करने के मामले में सांभर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी किए गए पीतल के बर्तन भी बरामद किए हैं।

थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार यादव ने बताया कि वह दिन में कई दिनों तक सूने पड़े मकानों की रेकी करता था, फिर रात्रि में मकानों में घुसकर पुराने बर्तन, लोहे का सामान व अन्य सामान जो भी मिलता था उनको चोरी कर ले जाता था।

युवक शराब, गांजा पीने का का आदी है एवं मौज मस्ती व नशे का शौक पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देता है। थाना सांभरलेक पर दर्ज प्रकरण में अज्ञात चोरों को गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूद शिवलाल बैरवा के निर्देशन में पुलिस उप अधीक्षक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में तथा थानाधिकारी सांभरलेक राजेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर, गठित टीम



सांभर पुलिस ने चोरी के मामले में युवक को गिरफ्तार किया।

द्वारा आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा वारदात करने वाले

अज्ञात आरोपी का पता लगाकर उसे दबिश देकर महज 48 घण्टे में

■ **पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए पीतल के बर्तन बरामद किए**

■ **आरोपी युवक शराब, गांजा पीने का आदी है एवं मौज मस्ती व नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था**

गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से चोरी किया हुआ माल पुराने इस्तेमाल किये पीतल के बर्तनों को भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी गुलफाम खान पुत्र अब्बू गुलफामनिवासी शहीद पुनम चन्द मार्ग, बरडौती मोहल्ला सांभरलेक का ही रहने वाला है।

बिजयनगर ब्लैकमेल कांड मामले में स्टे

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अजमेर के बिजयनगर ब्लैकमेल कांड के पांच आरोपियों के परिजनों की संपत्ति तोड़ने पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामलों की सुनवाई 11 मार्च को तय की है। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश शकीर व चार अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में सैयद सआदत अली ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं के घर के युवाओं को पुलिस ने कथित रूप से हुए ब्लैकमेल कांड में फंसाया है। अभी सभी आरोपी गिरफ्तार व न्यायिक अभिरक्षा में हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के घर नोटिस चप्पा कर कब्जा हटाने की चेतावनी दी है। याचिका में कहा गया कि यह संपत्ति मामले में गिरफ्तार किए गए युवाओं की ना होकर याचिकाकर्ताओं की है। ऐसे में उसकी संपत्ति पर कार्रवाई करना विधि विरुद्ध है। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ताओं के घर पर चप्पा किए गए नोटिस ब्लैकमेल कांड में पकड़े गए युवाओं के नाम से हैं और उनका इन संपत्तियों पर किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है।

बब्बर खालसा का आतंकी लजर मसीह कौशंबी जिले में पकड़ा गया

कौशंबी, 06 मार्च। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर कौशंबी जिले से बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के एक कथित सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। आतंकवादी की पहचान पंजाब के अमृतसर के रामदास क्षेत्र के कुलियाण गांव के रहने वाले संदिग्ध आतंकी लजर मसीह के रूप में हुई है। आतंकी की गिरफ्तारी को लेकर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि आतंकी लजर हाल ही में संपन्न हुए प्रयागराज महाकुंभ में आतंकी घटना करने की फिराक में था। डीजीपी प्रशांत कुमार ने गिरफ्तार आतंकी को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि आतंकी लजर लगातार पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के साथ सम्पर्क में था। पाकिस्तान में बैठे कुछ हैडलर उसे लगातार ड्रोन से गोला बारूद और असला भी भेज रहे थे। प्रशांत कुमार ने प्रैस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि लजर यूपी के प्रयागराज जिले में संपन्न हुए महाकुंभ में कोई बड़ी आतंकी घटना करना चाहता था। इसके बाद वो पुर्तगाल भागने की फिराक में था।

विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा में चूक को ब्रिटेन ने गंभीर माना

जयशंकर लंदन के चौथम हाउस से जब बाहर निकल रहे थे, तब एक व्यक्ति ने दौड़कर पुलिस के सामने, भारतीय ध्वज फाड़ा था

लंदन, 06 मार्च। जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक मामले पर भारत की कड़ी आपत्ति को यूके ने भी गंभीरता से लिया है। ब्रिटेन ने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की सुरक्षा में चूक अस्वीकार्य है। यूके ने अपने बयान में कहा है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से काम किया। "हम अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप अपने सभी राजनयिक आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सुरक्षा बाधित करने के इस तरह के प्रयासों की हम कड़ी निंदा करते हैं।"

ज्ञातव्य है कि एस जयशंकर बुधवार को लंदन के चौथम हाउस में चर्चा के बाद बाहर निकल रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनकी कार की ओर दौड़ा और पुलिस अधिकारियों के सामने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फाड़ दिया। ब्रिटेन ने इस घटना की

■ ब्रिटेन ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करने का कोई भी प्रयास अस्वीकार्य है।

कड़ी निंदा की है, जिसमें खालिस्तानी चरमपंथियों के एक समूह ने लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा को बाधित करने का प्रयास किया। इस सुरक्षा उल्लंघन को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और इस मामले में ब्रिटिश सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करने का कोई भी

प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है। गुरुवार को जारी कार्यालय के बयान में कहा गया, "हम विदेश मंत्री की यूके यात्रा के दौरान कल चौथम हाउस के बाहर हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। हालांकि यूके शक्तिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को डराने, धमकाने या बाधित करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"

"घटना के संबंध में यूके की यह प्रतिक्रिया भारत सरकार द्वारा सुरक्षा उल्लंघन पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने और "भद्रका गतिविधियों" की निंदा करने के कुछ घंटों बाद आई है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में "अलगाववादियों और चरमपंथियों" के छोटे समूह द्वारा "लोकतांत्रिक स्वतंत्रता" के दुरुपयोग की निंदा की और यूके के लिए एक सख्त संदेश भी जारी किया था।

आबू रोड के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हैड कांस्टेबल विनोद लाम्बा ने बताया कि मृतकों के शवों को बाहर निकालने के लिए कार के दरवाजे तोड़े गए। करीब 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका।

सड़क हादसे में मारे गए सभी लोग जालोर जिले के निवासी और और प्रजापत समाज से हैं। हादसे में एक परिवार के नारायण प्रजापत (58) पुत्र नरसाराज, उनकी पत्नी पोशी देवी (55) व उनका पुत्र दुष्यंत (24) निवासी कुम्हारों का वास, जालोर, सहित, चालक कालुराम (40) पुत्र प्रकाश चांदराई जालोर, यशराम (4) पुत्र कालुराम चांदराई जयदीप पुत्र पुखराज प्रजापत शामिल हैं। दरिया देवी (35) पत्नी पुखराज निवासी जालोर, घायल हैं, जिन्हें आबूरोड राजकीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सिरोंही रैफर किया गया। कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की मौत हो गई।

जिला कलैक्टर अल्पा चौधरी, एसपी अनिल कुमार बेनीवाल ने घटना पर दुःख जताया व घटना के बारे में आवश्यक जानकारी ली। शाम को जालोर निवासी नारायण सहित अन्य का गमगान माहौल में अंतिम संस्कार किया गया।

पूरे परिवार की अर्थियां जब एक साथ उठीं तो हर किसी के आंखों में आंसू नजर आए।

'हजारों भारतीय युवाओं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अमेरिकन आप्रवासन (इमिग्रेशन) व्यवस्था में बैकलॉग की स्थिति यह है कि अनेक लोगों को स्थायी नागरिकता के लिये लम्बी प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ आवेदनों में तो 12 से 100 वर्ष तक प्रतीक्षा करना सम्भावित बताया गया। टैक्सस की एक अदालत के हाल ही के एक फैसले के अनुसार, डैफर्ड एक्शन फॉर चिल्ड्रन अराइवल्स (डीएसीए) प्रोग्राम के तहत, नये आवेदकों के लिये वर्क परमिट ब्लॉक कर दिये गये हैं। इस फैसले से स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। डीएसीए, अनडॉक्यूमेंटेड युवाओं को डिपेंडेंट्स से दो साल अस्थायी संरक्षण प्रदान करता है, जिसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है, इनमें वे युवा भी शामिल हैं, जिनका, 21 वर्ष की उम्र के बाद, डिपेंडेंट स्टेटस समाप्त हो चुका है। इस प्रावधान के बिना, बहुत से भारतीय युवाओं को अनिश्चित भविष्य का डर सता रहा है।

यू.एस. सीनेटर बर्नी सैंडर्स, जो एक अल्पकालीन प्रगतिशील नेता हैं, ने इस साल के शुरू में एच-वन बी वीसा प्रोग्राम की आलोचना की थी तथा यह तर्क दिया था कि यह प्रोग्राम मुख्यतः कॉर्पोरेशन्स के लिये लाभदायक है क्योंकि वे अमेरिकन को काम पर रखने के बजाय, कम वेतन वाले विदेशी कामगारों को लेते हैं।

सैंडर्स ने कहा था, "एच-वन बी प्रोग्राम का मुख्य काम "सर्वोत्तम तथा कुशाग्र बुद्धि वाले लोगों को नौकरी देना नहीं, बल्कि अच्छा वेतन मांगने वाले अमेरिकन को के स्थान पर, कम वेतन

स्वीकार करने वाले बाहरी देशों के हजारों लोगों को नौकरी पर रखना है। इन लोगों के साथ अनुबन्धित कर्मचारियों की तरह व्यवहार किया जाता है।"

सैंडर्स ने लेकन रिसे एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था, जिसका उद्देश्य एच-वन बी वीसा फीस को दुगुना करना था, ताकि अमेरिकन 370 मिलियन डॉलर प्रतिवर्ष अर्जित कर सके तथा एसटीईएम फील्ड में अमेरिकन छात्रों को करीब 20,00,000 छात्रवृत्तियाँ दे सके। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया था कि एच-वन बी वर्कर्स वेतन बढ़ाकर, कम से कम औसत स्थानीय वेतन के बराबर कर देना चाहिये, जिससे कम्पनियों को अमेरिकन वेतन में कटौती से रोक जा सके। सैंडर्स चाहते थे कि टेक्सा के मालिक एलन मस्क तथा भारतीय अमेरिकन उद्यमी विवेक रामास्वामी जैसे अरबपति एच-वन बी प्रोग्राम में आर्थिक सहयोग दें।

उन्होंने कहा, "दुनिया के सबसे अधिक धनवान, एलन मस्क तथा अन्य-खरबपति जोर देते हुये कहते हैं कि अत्यधिक कुशल वर्कर्स की कमी के कारण, एच-वन बी प्रोग्राम बहुत उपयोगी हो गया है। मेरी नजर में, ये लोग पूरी तरह गलत हैं।

इकांनॉमिक पॉलिसी इन्स्टीट्यूट के डेटा का हवाला देते हुये, उन्होंने कहा था कि 2022 से 2023 के बीच, 30 शीर्षस्थ एच-वन बी नियोक्ताओं ने 85000 अमेरिकन वर्कर्स का नौकरी से हटाकर, 34000 से अधिक गैस्ट वर्कर्स नौकरी पर रख लिये थे।

जब इंदिरा गांधी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एक महिला पत्रकार, जो एक मीटिंग कवर कर रही थीं, को वाशरूम जाने के लिये 24 अकबर रोड स्थित पुराने मुख्यालय भवन में जाना पड़ा।

नये मुख्यालय का काम-काज एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह चल रहा है तथा उसका कार्यकर्ताओं और नेताओं से कोई सम्पर्क नहीं रहा है, जिनसे मिलकर कांग्रेस पार्टी बनी है।

ऐसे समय, जब पार्टी के लिए अपने दरवाजे खुले रखना तथा कार्यकर्ताओं और नेताओं को अंदर आने देना जरूरी है, पार्टी की चिन्तन प्रक्रिया इसके ठीक उलट चल रही है।

इस व्यवस्था के लिये कौन और क्यों जिम्मेदार है?

यह व्यवस्था न केवल घबराहट पैदा करने वाली है, बल्कि साजिशपूर्ण प्रतीत हो रही है। बहुत से नेता इस व्यवस्था तथा बदलाव का दोषारोपण महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल पर कर रहे हैं। लेकिन क्या वे यह सब राहुल गांधी की सहमति के बिना कर सकते हैं?

क्या राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को कुछ भी करने की छूट दे रखी है? तथा इस पूरे व्यवस्था-परिवर्तन में प्रियंका गांधी की भूमिका क्या है?

वे बिना विभागीय महासचिव हैं, लेकिन नये मुख्यालय की हाउस कीर्षा में लगी रहती हैं।

क्या गांधी परिवार को इस बात की जानकारी है कि वह उसके अपने कार्यकर्ताओं से किस प्रकार दूर होते जा रहे हैं, या फिर उन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है?

नेताओं में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि एआईसीसी में विभिन्न पदों पर बैठे नेता किस तरह से अपने पद सुरक्षित बनाये रखने में लगे हुये हैं तथा वे नहीं चाहते कि इन पदों तक अन्य लोग पहुँच सकें। बड़ी दिलचस्प, किन्तु घबराहट पैदा करने वाली स्थिति है। पार्टी इस समय घोर असंतोष की जकड़ में है। नेतागण सवाल कर रहे हैं कि निर्णय किस तरह लिये जा रहे हैं तथा पार्टी लगातार चुनाव क्यों हारती जा रही है और इस स्थिति के बावजूद, सब कुछ व्यवस्थित और ठीक करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा।

हज यात्रा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है। ऐसे में नीतिगत विषय में कौट द्वारा कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं है।

फ्रांस ने अच्छी तरह से अमेरिका को अंगूठा दिखाया और दादागिरी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले ही यह निर्णय कर लिया था कि परमाणु सुरक्षा और रक्षा कवच का विस्तार यूरोप के अन्य देशों तक करने के लिए रणनीतिक वार्ता शुरू की जानी चाहिए। यूरोप में फ्रांस एवं ब्रिटेन ही हैं, जिनके पास अन्य देशों, खासकर रूस, के हमले से बचने के लिए परमाणु हथियारों का भंडार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जैलैंस्की की टुम्प से हुई विनाशकारी मुलाकात के बाद लंदन में यूरोपियन देशों की बैठक बुलाई थी।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिका से अलग होकर यूक्रेन की शांति योजना पर स्वतंत्र रूप से काम करने की मांग टुम्प के समक्ष चुनौती पेश कर दी है। यह योजना एक छोटे समूह द्वारा बनाई जाएगी, जिसमें फ्रांस, यू.के., जर्मनी और पश्चिमी यूरोप के कई प्रमुख समूह शामिल हैं।

■ दूसरी और अमेरिका अभी भी जैलैंस्की द्वारा वाइट हाउस में की गई "धृष्टता" के लिये प्रतिशोध लेने की फिराक में है तथा यूक्रेन युद्ध की खुफिया जानकारी साझा करने से इन्कार कर दिया है।

■ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यूरोप व अमेरिका के बीच जो विश्वास व मित्रता का रिश्ता था, वो इतना बुरा छिन्न-भिन्न पहले कभी नहीं हुआ था। पर, अब क्या फ्रांस की नई भूमिका से अमेरिका यूरोप से एकदम कट सा नहीं गया।

यह टुम्प के रूसियों से स्वतंत्र रूप से सम्पर्क साधने और यूक्रेन वॉर खत्म करने की कोशिश के एकदम उलट है। टुम्प ने अपनी मुहिम में किसी भी यूरोपियन देश को साथ नहीं लिया था। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल सऊदी अरब में रूस के प्रतिनिधियों से मिला था। इसमें यूरोपियन देश तो दूर यूक्रेन का भी प्रतिनिधित्व नहीं था।

टुम्प ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात किए बिना ही मिनरल डील भी घोषित कर दी थी। टुम्प एक दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के अपने चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए यह सब कर रहे थे ताकि वे यह साबित कर सकें कि वे सुप्रीम डील मेकर हैं।

पर अमेरिकन्स के अक्खड़ रूख के कारण इन प्रयासों पर रोक लग गई है।

अब फ्रांस ने इसका कूटनीतिक लाभ उठाकर अमेरिका से अलग अपना स्वतंत्र रूख घोषित कर दिया है। मैक्रों ने कहा है कि शांति होने तक यूरोपियन सैनिक यूक्रेन में ही डटे रहेंगे।

अमेरिका के राष्ट्रपति को, आक्रमण के विरुद्ध लड़ने के अपने संकल्प को दिखाने के लिए यूरोपीय देश यूक्रेन और युद्ध में घिरे उसके राष्ट्रपति को और अधिक समर्थन दे रहे हैं। फ्रांस द्वारा उठाए गए कदम अमेरिका की शांति प्रक्रिया से और यूरोप के कूटनीतिक क्षेत्र से एक तरह से अलग-थलग कर रहे हैं।

हालांकि, फ्रांस के राष्ट्रपति कूटनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन, यह आसान नहीं होगा। अमेरिका, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जैलैंस्की को, वाइट हाउस में अमेरिका के खिलाफ बोलने की धृष्टता तथा आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करने के लिए सजा देने की अपनी योजनाओं पर

आगे बढ़ रहा है।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने के साथ-साथ खुफिया जानकारी भी साझा नहीं करने के आदेश दिए हैं। अमरीकी, बदला लेने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने उनकी हर बात मानने से इन्कार कर दिया। इसके कारण, रूस का प्रतिरोध करने की यूक्रेन की क्षमता सीमित हो गई है। इस बीच, रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध अपनी आक्रामकता को बढ़ा दिया है तथा यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है।

परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता दर्शाने के लिए और यूरोप के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए साहसी व निडर दांव खेला है। यह अमेरिका पर 1946, दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जो भरोसा बना था और यूरोपियन देशों की निर्भरता बढ़ी थी, उसे छीन लेने जैसा है।

तमिलनाडु ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुये कहा कि उनकी सरकार अन्य भाषाओं का भी सम्मान करती है। "अगर आप अपनी भाषा को प्रेम और सम्मान देते हैं, तो आप अन्य भाषाओं के प्रति भी वैसा ही करें। मुझे यकीन है कि भैया जी मुझसे सहमत होंगे।"

जेशी के बयान पर आई कड़ी प्रतिक्रियाओं के एक दिन बाद, भैया जी ने स्वयं "ऑन रिकार्ड" स्पष्टीकरण दिया कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। "मराठी मेरी जन्मजात भाषा है तथा मुझे इस पर गर्व है। मराठी मुम्बई और महाराष्ट्र की भाषा है, इस बारे में दो राय नहीं हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग मुम्बई में मिलजुलकर रहते हैं।"

घाटकोपर के एक समारोह में, अपने भाषण के सम्बंध में भैया जी ने पुनः स्पष्टीकरण दिया: "मुम्बई में एक भाषा नहीं बोली जाती है। मुम्बई के प्रत्येक हिस्से में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। घाटकोपर क्षेत्र की भाषा गुजराती है। इसलिये, अगर आप मुम्बई में रह रहे हैं तो आपको मराठी सीखना जरूरी नहीं है।"

ठाकरे ने कहा कि भैयाजी का बयान मुम्बई को विभाजित करने के आरएसएस और भाजपा के छिपे हुये एजेंडा को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा, "मराठी मानुष" (सबका) स्वागत कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी उसे हानि पहुँचा सकता है।"

MARUTI SUZUKI

NEXA

COLOUR YOUR JOURNEYS WITH INSPIRATION.

Book any NEXA Car before 14th March and avail additional benefits of up to ₹ 10 000**

CREATE. INSPIRE.



3 years 100 000 km WARRANTY*
EXTENDABLE UPTO 6 YEARS

CONSUMER OFFERS OF UP TO ₹ 1 00 000*

EXCHANGE BONUS OF UP TO ₹ 1 00 000*

PER LAKH EMI STARTING FROM ₹ 1 470*

ADDITIONAL SCRAPPAGE BONUS UP TO ₹ 15 000 IS AVAILABLE AGAINST VALID CERTIFICATE OF DEPOSIT.



SCAN TO CONNECT TO A SHOWROOM NEAR YOU



E-BOOK TODAY @ WWW.NEXAEXPERIENCE.COM

Contact us at
1800-200-6392
1800-102-6392

**For detailed T&C kindly visit nearest dealership. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice and offers may vary across variants. *Offer includes consumer offer, exchange bonus and institutional or rural offer (wherever applicable) on select models/variants. Finance is at the sole discretion of financier. **3 years or 100 000 km - whichever is earlier. Scrupage offer valid for limited period only and is brought to you by Maruti Suzuki Toyota India Private Limited (a joint venture company between Maruti Suzuki India Ltd and Toyota Tsusho Group). Above offers are valid till 31st March 2025. Black glass shade on the vehicle is due to the lighting effect. Images used are for illustration purposes only. Car color may vary due to printing on paper.

राष्ट्रदूत (एचयूपीएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा बतन प्रेस, जी-1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौन सिटी, जिला करौली से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2008/27147 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032, फैक्स: 0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुमाना हाऊस, हनुमान हत्या, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आर्यभट्ट मैन रोड आर्यभट्ट, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स: 0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस थयम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908